

विभिन्न संगठनों द्वारा नीतियां



भारत में उच्च शिक्षा की नियामक रूपरेखा

1. नीति बनाने वाली संस्थाएँ/अभिकरण

(क) उच्च शिक्षा विभाग : उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, योजना और नीति दोनों के संदर्भ में अर्थव्यवस्था में उच्च शिक्षा क्षेत्र की बुनियादी अवसंरचना के समग्र विकास के लिए उत्तरदायी है। एक सुनियोजित विकास प्रक्रिया के तहत, विभाग विश्व स्तर के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और विभिन्न अन्य निजी संस्थानों के माध्यम से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुगमता और गुणात्मक सुधार के विस्तार की देखभाल करता है। उच्च शिक्षा विभाग की विभिन्न भूमिकाएँ और उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

- सभी विधियों (नियमित, ऑनलाइन, दूरस्थ कार्यक्रम) के माध्यम से पहुंच का विस्तार करके सकल नामांकन अनुपात (वर्ष 2020 तक 30%) बढ़ाना।
- समाज के उन वर्गों की भागीदारी को बढ़ावा देना जिनका सकल नामांकन अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम है।
- शैक्षणिक सुधारों को बढ़ावा देना और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना।
- नए शिक्षण संस्थानों की स्थापना करके संस्थानों की संख्या बढ़ाना।
- मौजूदा संस्थानों को बेहतर बनाना।
- उच्च शिक्षा में प्रौद्योगिकी-संचालित कक्षाओं के उपयोग को बढ़ावा देना।
- व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास के विकास को बढ़ाना।
- भारतीय भाषाओं में शिक्षा का विकास करना।
- उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग/लिंक-अप को बढ़ाना।

(ख) राज्य उच्च शिक्षा परिषदें

- कई राज्यों ने राज्यों में उच्च शिक्षा संस्थानों के उचित कामकाज के लिए दिशानिर्देश और मानदंड प्रदान करने के लिए परिषदों और सलाहकार बोर्डों की स्थापना की है।
- ये परिषद राज्य के भीतर उच्च शिक्षा में सरकारी विश्वविद्यालयों और सर्वोच्च नियामक एजेंसियों की भूमिकाओं का समन्वय करती हैं। निम्नलिखित राज्यों ने उच्च शिक्षा परिषदें गठित की हैं :
 - आंध्र प्रदेश
 - केरल
 - तमिलनाडु
 - पश्चिम बंगाल

- उत्तर प्रदेश
- अरुणाचल प्रदेश,
- अगरतला
- हिमाचल प्रदेश

(ग) केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (CABE) : यह नीति निर्माण सहित शिक्षा के क्षेत्र में संघ और राज्यों के बीच समन्वय और सहयोग के लिए स्थापित किया गया था। यह 1920 में स्थापित किया गया था और 1923 में भंग कर दिया गया था। इसे 1935 में फिर से पुनर्जीवित किया गया था और तब से यह अस्तित्व में है।

(घ) भारतीय विश्वविद्यालय संघ (AIU)

- यह विदेशी विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या, क्रेडिट और मानकों का मूल्यांकन करता है और भारतीय महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान किए जाने वाले विभिन्न पाठ्यक्रमों के साथ इसकी तुलना करता है।
- यह संघ एक ऐसे निकाय के रूप में भी कार्य करता है जो भारत के विश्वविद्यालयों द्वारा दिए गए विभिन्न डिग्री/डिप्लोमा को मान्यता देता है, जिन्हें भारत में महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में उच्च पाठ्यक्रमों में प्रवेश के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), नई दिल्ली और विदेशों में मान्यता प्राप्त है।
- पहले इसका नाम अंतर-विश्वविद्यालय बोर्ड था और समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत 29 सितंबर, 1967 को समिति के रूप में इसके पंजीकरण के साथ एक कानूनी दर्जा प्राप्त किया।
- 1973 में इसका नाम बदलकर भारतीय विश्वविद्यालय संघ कर दिया गया।

2. विनियमन आधारित अभिकरण

उच्च शिक्षा विभाग के अधीन शीर्ष स्तरीय निकाय (नियामक निकाय/अनुसंधान परिषद) हैं, जो भारत में उच्च शिक्षा के लिए उत्तरदायी हैं। इन निकायों को मुख्य रूप से नियामक निकायों और अनुसंधान परिषदों में विभाजित किया जा सकता है।

उच्च शिक्षा में महत्वपूर्ण नियामक निकाय हैं :

- अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE)
- वास्तुकला परिषद (COA)
- भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद (ICHR)
- भारतीय दर्शन अनुसंधान परिषद (ICPR)

- भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICSSR)
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC)

प्रत्यायन आधारित निकाय : प्रत्यायन के लिए दो निकाय हैं:

(क) राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (NBA)

- इसकी शुरुआत एआईसीटीई (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद) द्वारा एआईसीटीई अधिनियम की धारा 10 (न) के अंतर्गत वर्ष **1994** में की गई थी।
- इसे एआईसीटीई परिषद द्वारा अनुशंसित निर्दिष्ट मानदंडों और मानकों के अनुसार तकनीकी संस्थानों और कार्यक्रमों के आवधिक मूल्यांकनों के लिए स्थापित किया गया था।
- एनबीए 7 जनवरी 2010 से एक **स्वायत्त निकाय** के रूप में अस्तित्व में आया, जिसका उद्देश्य तकनीकी संस्थानों द्वारा प्रदान किए जाने वाले कार्यक्रमों के प्रत्यायन के तंत्र के माध्यम से, विशेष रूप से व्यावसायिक और तकनीकी कार्यक्रमों, अर्थात् इंजीनियरिंग, प्रबंधन, फार्मेसी, वास्तुकला और आतिथ्य में गुणवत्ता आश्वासन और शिक्षा प्रासंगिकता प्रदान करना है।
- एनबीए ने प्रत्यायन के लिए एक नई प्रक्रिया, मानदंड और प्राचल शुरू किए हैं।

(ख) राष्ट्रीय मूल्यांकन और मान्यता परिषद (NAAC)

- एनएसीसी की स्थापना 1994 में यूजीसी के एक स्वायत्त संस्थान के रूप में बेंगलूर, कर्नाटक में अपने मुख्यालय के साथ की गई थी।
- एनएसीसी के अधिदेश में गुणवत्ता आश्वासन को उच्च शिक्षा संस्थानों (HEI) के कामकाज का एक अभिन्न अंग बनाना शामिल है।
- यह अपनी सामान्य परिषद (GC) और कार्यकारी समिति (EC) के माध्यम से कार्य करता है, जिसमें नीति निर्माता, शैक्षिक प्रशासक और भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली के वरिष्ठ शिक्षाविद शामिल हैं।
- सामान्य परिषद के अध्यक्ष - यूजीसी के अध्यक्ष
- कार्यकारी समिति के अध्यक्ष - सामान्य परिषद (NAAC) के अध्यक्ष द्वारा नामित प्रख्यात शिक्षाविद।
- समय-समय पर गठित परामर्शक और सलाहकार समितियों द्वारा एनएसीसी की सहायता की जाती है।

उच्च शिक्षा अनुदान एजेंसी (HEFA):

उच्च शिक्षा अनुदान एजेंसी (HEFA) केनरा बैंक और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की संयुक्त उद्यम कंपनी है। HEFA भारत के प्रमुख शैक्षिक संस्थानों में शैक्षिक अवसंरचना और अनुसंधान एवं विकास के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

HEFA का गठन सितंबर 2016 में उच्च शिक्षा संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मंत्रिमंडल की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद किया गया था।

इसे केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा दिए गए अनुदान के अलावा बनाया गया है। इसे 2000 करोड़ रुपये की पूंजी के लिए अधिकृत किया गया है।

HEFA एक गैर-लाभकारी संगठन है जो बाजार से निधियां लेगा और उन्हें दान और निगमित सामाजिक दायित्व (CSR) फंड के साथ पूरक करेगा। उपलब्ध कराए गए धन का उपयोग शीर्ष संस्थानों में बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए किया जाएगा और आंतरिक उपार्जन के माध्यम से सेवित किया जाएगा।

HEFA के तहत वित्त पोषण प्रमुख शिक्षा संस्थानों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए भारत सरकार द्वारा वर्तमान अनुदान सहायता का स्थान लेगा।

अनुदान दृष्टिकोण की तुलना में HEFA संस्थानों की बड़ी आवश्यकताओं को निधि देने में सक्षम होगा। शीर्ष श्रेणी के बुनियादी ढांचे को त्वरित समय में बनाया जा सकता है ताकि देश को तेजी से समय सीमा में अपने जनसांख्यिकीय लाभांश की क्षमता का एहसास हो सके।

संबंधित मंत्रालयों द्वारा निर्दिष्ट/वित्तपोषित सभी शैक्षणिक संस्थान HEFA से अपने पूंजीगत व्यय के वित्तपोषण के लिए पात्र होंगे।

यह ऋण सीमा के लिए आधार बनाता है जिसका उपयोग संस्था द्वारा आवश्यक पूंजी और अनुसंधान परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए किया जा सकता है। मूल भाग को बढ़ी हुई राशि से चुकाया जाता है और ब्याज सरकार द्वारा पूरा किया जाता है। यह संस्था के लिए ब्याज मुक्त राशि है और सुविधाएं प्रदान करती है। यह संस्था विश्व स्तरीय आवश्यक अनुसंधान बुनियादी ढांचे का निर्माण करने के लिए है।

शिक्षा रैंकिंग


1) विश्व विश्वविद्यालय रैंकिंग

हाल ही में विश्व विश्वविद्यालय रैंकिंग 2020 के संबंध में एक घोषणा में छह भारतीय विश्वविद्यालयों को शीर्ष 500 में शामिल किया गया है। भारतीय संस्थानों में, आईआईटी बॉम्बे

और आईआईटी दिल्ली को पछाड़ते हुए, आईआईएससी बेंगलोर के साथ आईआईटी रोपड़ को पहला स्थान दिया गया था।

किसी भी भारतीय संस्थान ने दुनिया के शीर्ष 300 संस्थानों में रैंक प्राप्त नहीं की।

IIT-ROPAR MAKES STRONG DEBUT

Indian universities in top 500*		
University	2020	2019
Indian Institute of Science	301-350	251-300
IIT, Ropar	301-350	NR
IIT, Indore	351-400	351-400
IIT, Bombay	401-500	401-500
IIT, Delhi	401-500	501-600
IIT, Kharagpur	401-500	501-600
		
Global best	2020	2019
University of Oxford (UK)	1	1
California Institute of Technology (US)	2	5
University of Cambridge (UK)	3	2
Stanford University (US)	4	3
Massachusetts Institute of Technology (US)	5	4
HIGHLIGHTS		
<ul style="list-style-type: none">➤ No Indian institutions in the top 300➤ Ranking of Indian Institute of Science declines, marking first time that it is not in top 300 since 2012➤ IIT-Ropar made it to top 350 in its debut participation➤ In 2019, there were 5 Indian universities in top 500➤ In 2020, there are 6 Indian universities in top 500➤ Overall, 56 Indian universities feature in the table, up from 49 last year in a list of 1,300 universities➤ India fifth most-represented nation in the rankings➤ China is home to top two universities in Asia for first time➤ University of Oxford comes top for the fourth year in a row; California Institute of Technology (Caltech) placed second		
Individual ranks are allotted till rank 200; * Post 200th rank, institutions are placed in a cohort of 50 ranks		

टाइम्स उच्च शिक्षा विश्व विश्वविद्यालय रैंकिंग 2020 :

- इसमें 92 देशों में लगभग 1,400 विश्वविद्यालय शामिल हैं जिससे इसे सबसे बड़ा और सबसे विविध विश्वविद्यालय रैंकिंग माना जाता है।
- शिक्षण, अनुसंधान, ज्ञान हस्तांतरण और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण में संस्थान के प्रदर्शन को मापने के लिए 13 सावधानीपूर्वक जांच निष्पादन संकेतक हैं।
- पेशेवर सेवा फर्म PWC रैंकिंग के ऑडिट के लिए जिम्मेदार है, जिस पर छात्रों, शिक्षकों, सरकारों और उद्योग के विशेषज्ञों द्वारा विश्वभर में भरोसा किया जा रहा है

एनआईआरएफ (NIRF) :

- राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया और 29 सितंबर 2015 को एमएचआरडी मंत्री द्वारा इसका शुभारंभ किया गया।
- यह अवसंरचना पूरे देश में संस्थानों को रैंक करने के लिए एक कार्यप्रणाली की रूपरेखा तैयार करती है। विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों की रैंकिंग के लिए व्यापक मापदंडों की पहचान करने के लिए एमएचआरडी द्वारा गठित एक कोर समिति द्वारा समय सिफारिशों की व्यापक समझ से कार्यप्रणाली तैयार की गई है।
- मापदंड मोटे तौर पर "शिक्षण, अध्ययन और संसाधन," "अनुसंधान और व्यावसायिक व्यवहार," "स्नातक परिणाम," "आउटरीच और विशिष्टता," और "धारणा" को कवर करते हैं।
- इन मापदंडों को पांच समूहों में बांटा गया है और इन समूहों को कुछ निश्चित भारिता दी गई है।

एआरआईए (ARIAA):

- छात्रों और संकायों के बीच "नवाचार और उद्यमिता विकास" से संबंधित संकेतकों पर भारत के सभी प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों को व्यवस्थित रूप से रैंकिंग के लिए नवाचार उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग (ARIAA) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD), भारत सरकार की एक पहल है।
- विचारार्थ प्रमुख संकेतक
 - बजट और अनुदान सहायता।
 - अवसंरचना और सुविधाएं।
 - अवधारणा उत्पन्न करने और नवाचार के लिए जागरूकता, प्रोत्साहन और समर्थन।
 - उद्यमिता विकास के लिए प्रोत्साहन और समर्थन।

- नवीन अध्ययन विधियाँ और पाठ्यक्रम।
 - बौद्धिक संपदा उत्पादन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और व्यावसायीकरण।
 - संस्थान के प्रशासन में नवाचार।
-
- आईआईटी मद्रास ने 'सार्वजनिक वित्त पोषित संस्थान श्रेणी' में सबसे ऊपर है।
 - वेल्लोर प्रौद्योगिकी संस्थान, तमिलनाडु 'निजी संस्थान श्रेणी' में सबसे ऊपर है।

NIRF भारत रैंकिंग - 2016 इस रूपरेखा पर आधारित 04 अप्रैल 2016 को जारी की गई थी।

टिप्पणी : वर्ष 2019 में दी गई रैंकिंग NIRF रैंकिंग का चौथा संस्करण और ARIIA रैंकिंग का पहला संस्करण था।

परमार्थ योजना :

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा नई दिल्ली में 18 जुलाई 2019 को यूजीसी द्वारा शुरू किया गया। इस योजना का मूल उद्देश्य उच्च शिक्षा में गुणवत्ता आश्वासन को बढ़ावा देने के लिए प्रत्यायन आकांक्षी संस्थानों के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन और मूल्यांकन परिषद (नैक) को सलाह देना है।




समग्र शिक्षा योजना

- केंद्रीय बजट, 2018-19 के प्रस्ताव के अनुपालन में, सरकार प्री-स्कूल से कक्षा 12 वीं तक विभाजन के बिना स्कूली शिक्षा को समग्र रूप से व्यवहार करना चाहती है।
- एमएचआरडी के तहत, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने वर्ष 2018-19 से प्रभावी रूप से एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में स्कूल शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना-समग्र शिक्षा की शुरुआत की है।

Samagra Shiksha
Focus on Girl Education

- ◆ Empowerment of girls
- ◆ Upgradation of KGBVs.
- ◆ Self-defence training for girls from upper primary to higher secondary stage.
- ◆ Stipend for CWSN girls to be provided from Classes I to XII. – earlier only IX to XII.
- ◆ Enhanced Commitment to 'Beti Bachao Beti Padhao'



- इस योजना में सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और शिक्षक शिक्षा (टीई) की पूर्ववर्ती केंद्र प्रायोजित तीन योजनाओं को समाहित किया गया है ।
- समग्र शिक्षा स्कूल शिक्षा क्षेत्र के लिए एक व्यापक कार्यक्रम है जो प्री-स्कूल से 12वीं कक्षा तक विस्तारित है और इसका उद्देश्य स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी और समान गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है ।
- योजना का विजन पूर्व-विद्यालय, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक एक निरंतरता के रूप में 'स्कूल' की परिकल्पना करना है।

परीक्षा के लिए याद रखने हेतु महत्वपूर्ण लघुरूप

- **IGNTU-** इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय
- **NRP** - नेशनल रिसर्च प्रोफेसरशिप
- **NITTTR** - राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान
- **EdCIL**-एजुकेशनल कंसल्टेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड
- **AISHE**-अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण
- **PTR** -शिष्य-शिक्षक अनुपात
- **NBT**-राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत
- **CABE**- केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड
- **NAAC** -राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद
- **NIRF**- राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF): इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया है और 29 सितंबर 2015 को माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था।

Regulatory Framework of Higher Education in India

1. Policy making bodies/agencies

(a). Department of Higher Education: The Department of Higher Education, MHRD, is held responsible for the overall development of the basic infrastructure of the Higher Education sector in the economy, both in terms of planning and policy. Under a planned development process, the department looks after expansion of accessibility and qualitative improvement in the field of higher education, through world-class universities, college, and various other Private Institutions. **The different roles and objectives of the Department of Higher Education are:**

- To enhance the Gross Enrolment Ratio (30% by the year 2020) by expanding access through all modes. (Regular, Online, Distance programmes)
- To promote the participation of those sections of the society whose Gross Enrolment Ratio is lower than the national average.
- To promote academic reforms and to improve the quality of education
- To increase the number of institutions by setting up new educational institutions
- To improve the existing institutions.
- To promote the utilization of Tech-driven classes in Higher Education.
- To enhance the Development of Vocational Education and Skill Development.
- To develop education in Indian Languages.
- To increase the International Collaboration/Link-ups in the field of higher education

(b). State councils of higher education

- Many states have set up the councils and advisory boards to provide guidelines and norms for the appropriate functioning of the higher education institutions in the states.

- These councils coordinate the roles of government universities and apex regulatory agencies in higher education within the state. **Following states have set up councils of higher education:**

- Andhra Pradesh
- Kerala
- Tamil Nadu
- West Bengal
- U.P
- Arunachal Pradesh,
- Agartala
- Himachal Pradesh

(c). Central advisory board of education (CABE):

It was set up for coordination and cooperation between the union and the states in the field of education including policy making. It was established in 1920 and dissolved in 1923. It was revived again in 1935 and has been in existence ever since.

(d). Association of Indian Universities (AIU)

- It evaluates the courses, syllabi, credits, and standards of foreign Universities and compares it with the various courses offered by Indian colleges/universities.
- This association also acts as a body that recognizes the different degrees/diplomas awarded by the universities in India, which are recognized by the University Grants Commission (UGC), New Delhi, and abroad for the purpose of admission to the higher courses in colleges/universities in India.
- Earlier it was named The Inter-University Board and acquired a legal status with its registration as a Society under the Societies Registration Act, 1860, on September 29, 1967.
- It was renamed as Association of Indian Universities in 1973.

2. Regulation Based Agencies

There are Apex Level Bodies (Regulatory Bodies/Research Councils) under the Department of Higher Education, which are responsible for higher education in India. These bodies can be broadly divided into Regulatory Bodies and Research Councils.

Important Regulatory bodies in Higher Education are:

- All India Council of Technical Education (AICTE)
- Council of Architecture (COA)
- Indian Council of Historical Research (ICHR)
- Indian Council of Philosophical Research (ICPR)
- Indian Council of Social Science Research (ICSSR)
- University Grants Commission (UGC)

Accreditation Based Bodies: There are two bodies for accreditation:

(a). The National Board of Accreditation (NBA)

- It was initially established by AICTE (All India Council of Technical Education) under section 10(u) of AICTE act, in the year **1994**.
- It was established for periodic evaluations of technical institutions & programs according to specified norms and standards as recommended by AICTE council.
- NBA came into existence as an **autonomous body** from 7th January 2010, with the objective of quality assurance and Education relevance, particularly of the professional and technical programs, i.e., Engineering, Management, Pharmacy, Architecture, and Hospitality, through the mechanism of accreditation of programs offered by technical institutions.
- NBA has introduced a new process, criteria and parameters for accreditation.

(b). National assessment and accreditation council (NAAC)

- NAAC was established in 1994 as an autonomous institution of the UGC with its headquarters in Bangalore, Karnataka.

- The mandate of NAAC includes making quality assurance an integral part of the functioning of Higher Education Institutions (HEIs).
- It functions through its General Council (GC) and Executive Committee (EC) comprising policy makers, educational administrators, and senior academicians from the Indian higher education system.
- President of the GC - The Chairperson of the UGC
- Chairperson of the EC - eminent academician nominated by the President of GC (NAAC).
- NAAC is supported by the advisory and consultative committees constituted from time to time.

Higher Education Funding Agency (HEFA):

Higher Education Financing Agency (HEFA) is a joint venture company of Canara Bank and Ministry of Human Resource Development Govt. HEFA provides financial assistance for creation of educational infrastructure and R&D in India's premier educational Institutions.

HEFA was set in September 2016 after receiving the Cabinet approval to provide financial assistance to institutes of higher education.

It is made in addition to grants given by Union Ministry of Human Resources Development. It has authorised capital of Rs. 2000 crore.


HEFA is a not-for-profit organisation that will leverage funds from market and supplement them with donations and Corporate Social Responsibility (CSR) fund. The funds provided will be used to finance improvement in infrastructure in top institutions and will be serviced through internal accruals.

The funding under HEFA will replace the current grant assistance by GOI for infrastructure projects in premier educational institutions.

HEFA would be able to fund larger basket of institutions as compared to grants approach. Top class infrastructure can be created in quick time so that the country realises the potential of its demographic dividend in a faster time frame.

All the Educational Institutions set up/funded referred by concerned ministries would be eligible for financing their capital expenditure from HEFA.

This forms basis for credit line which can be used by institution for creating required capital and research assets. The Principal portion is repaid from escrowed amount and interest is met by Government. For institution, this is interest-free amount and gives facilities. o institution to build the required research infrastructure of world class.

IIT-ROPAR MAKES STRONG DEBUT		
Indian universities in top 500*		
University	2020	2019
Indian Institute of Science	301-350	251-300
IIT, Ropar	301-350	NR
IIT, Indore	351-400	351-400
IIT, Bombay	401-500	401-500
IIT, Delhi	401-500	501-600
IIT, Kharagpur	401-500	501-600
		
Global best	2020	2019
University of Oxford (UK)	1	1
California Institute of Technology (US)	2	5
University of Cambridge (UK)	3	2
Stanford University (US)	4	3
Massachusetts Institute of Technology (US)	5	4
HIGHLIGHTS		
<ul style="list-style-type: none"> ➤ No Indian institutions in the top 300 ➤ Ranking of Indian Institute of Science declines, marking first time that it is not in top 300 since 2012 ➤ IIT-Ropar made it to top 350 in its debut participation ➤ In 2019, there were 5 Indian universities in top 500 ➤ In 2020, there are 6 Indian universities in top 500 ➤ Overall, 56 Indian universities feature in the table, up from 49 last year in a list of 1,300 universities ➤ India fifth most-represented nation in the rankings ➤ China is home to top two universities in Asia for first time ➤ University of Oxford comes top for the fourth year in a row; California Institute of Technology (Caltech) placed second 		
Individual ranks are allotted till rank 200; * Post 200th rank, institutions are placed in a cohort of 50 ranks		

EDUCATION RANKINGS

1) World University Ranking

Recently an announcement regarding the World University Rankings 2020, Six Indian Universities have made it among the top 500. Among Indian institutes, IIT Ropar was ranked first alongside IISc Bangalore, beating IIT Bombay and IIT Delhi.

No Indian institute secured a rank among the top 300 institutes of the world.

Times Higher Education World University Rankings 2020:

- It includes almost 1,400 universities across 92 countries it is considered as the largest and most diverse university rankings.
- There are 13 carefully calibrated performance indicators for measuring institution's performance across teaching, research, knowledge transfer and international outlook.
- The professional services firm PWC is responsible for auditing the rankings which is being trusted worldwide by students, teachers, governments and industry experts

NIRF:

- The National Institutional Ranking Framework (NIRF) was approved by the MHRD and launched by the MHRD minister on 29th September 2015.
- This framework outlines a methodology to rank institutions across the country. The methodology draws from the overall recommendations broad understanding arrived at by a Core Committee set up by MHRD, to identify the broad parameters for ranking various universities and institutions.
- The parameters broadly cover "Teaching, Learning and Resources," "Research and Professional Practices," "Graduation Outcomes," "Outreach and Inclusivity," and "Perception".
- These parameters have been grouped into five clusters and these clusters were assigned certain weightages.

ARIIA:

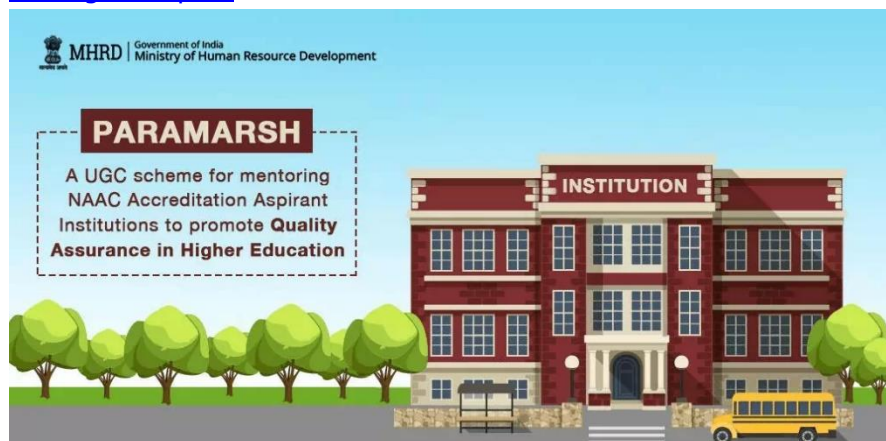
- **Atal Ranking of Institutions on Innovation Achievements (ARIIA)** is an initiative of Ministry of Human Resource Development (MHRD), Govt. of India to systematically rank all major higher educational institutions and universities in India on indicators related to “Innovation and Entrepreneurship Development” amongst students and faculties.
- Major Indicators for consideration
 - Budget & Funding Support.
 - Infrastructure & Facilities.
 - Awareness, Promotions & support for Idea Generation & Innovation.
 - Promotion & Support for Entrepreneurship Development.
 - Innovative Learning Methods & Courses.
 - Intellectual Property Generation, Technology Transfer & Commercialization.
 - Innovation in Governance of the Institution.
- IIT Madras has topped the ‘Public funded Institutions Category’.
- Vellore Institute of Technology, Tamil Nadu has topped the ‘Private Institutions Category’.

NIRF India Rankings - 2016 based on this framework were released on 4th April 2016

NOTE : The ranking given in the year 2019 were the fourth edition of NIRF Rankings and first edition of ARIIA ranking.

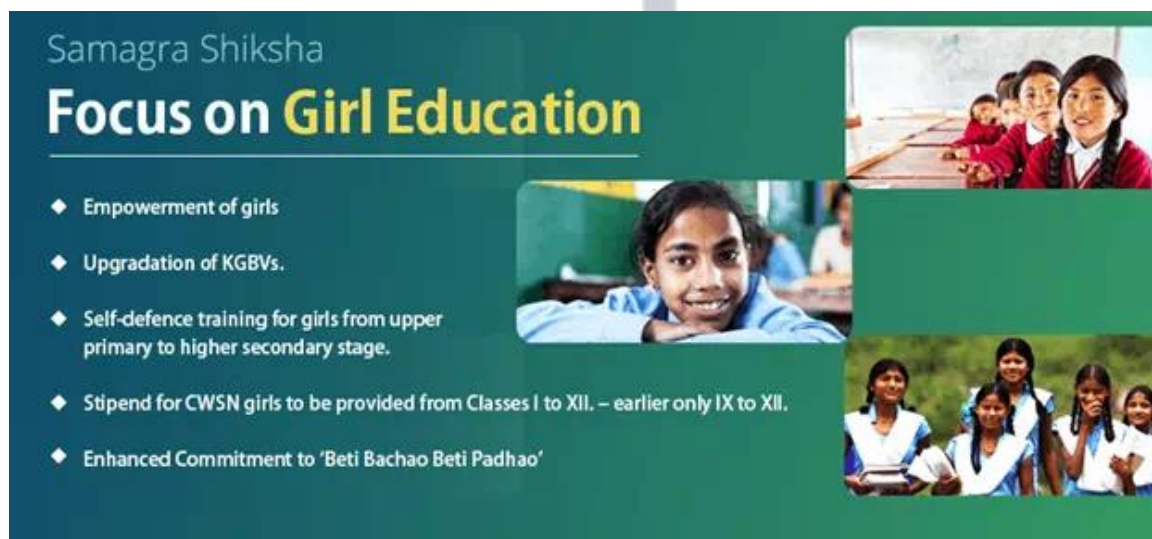
Paramarsh Scheme:

Launched by the UGC on 18th July 2019 in New Delhi by The Union Minister for Human Resource Development. The scheme basically aims towards Mentoring National Accreditation and Assessment Council (NAAC) Accreditation Aspirant Institutions to promote Quality Assurance in Higher Education.



Samagra Siksha Scheme

- In pursuance of the proposal of the Union Budget, 2018 - 19, The government wants to treat school education holistically without segmentation from pre-school to Class XII.
- Under the MHRD, the Department of School Education, and Literacy has launched the Samagra Shiksha - an Integrated Scheme for School Education as a Centrally Sponsored Scheme with effect from the year 2018 - 19.



- The scheme subsumes the three erstwhile Centrally Sponsored Schemes of Sarva Shiksha Abhiyan (SSA), Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA) and Teacher Education (TE).

- Samagra Shiksha is an overarching programme for the school education sector extending from pre-school to class XII and aims to ensure inclusive and equitable quality education at all levels of school education.
- The vision of the scheme is to envisage the 'school' as a continuum from pre-school, primary, upper primary, secondary to senior secondary levels.

Important Abbreviations to Remember for Exam

- **IGNTU**-The Indira Gandhi National Tribal University
- **NRP**-National Research Professorship
- **NITTTR** -National Institute of Technical Teachers Training & Research
- **EdCIL**-Educational Consultants of India Limited
- **AISHE** -All India Survey on Higher Education
- **PTR** -Pupil-Teacher Ratio
- **NBT**-National Book Trust of India
- **CABE**-Central Advisory Board of Education
- **NAAC**-National Assessment and Accreditation Council
- **NIRF**-National Institutional Ranking Framework (NIRF): It has been approved by the Ministry of HRD and was launched by Honourable Human Resource Development Minister on 29th September 2015.